का यह समाधान हो जाता है कि इसे श्रम न्यायालय/अधिकरण को निर्देशित करने का मामला है, तो वह इसे निर्देशित करती है । जहां यह विवाद को निर्देश के लिए नहीं भेजती, तो वह इसके कारणों को रिकार्ड करती है और संबंधित पक्षों को सूचित करती है । न्याय-निर्णयन के लिए अधिकरणों/श्रम न्यायालयों को ऐसे निर्देशन करने के लिए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन

2719. **श्रीमती रत्न कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें फसल बीमा योजना को केन्द्रीय सरकार की सहायता से लागू कर रही है,

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इस योजना को अब तक शुरु नहीं किया गया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना को लागू करने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा प्रति एकड़ उपज का आकलन करने के लिए अलग-अलग मानक अपनाये जा रहे हैं और विभिन्न राज्यों में इस संबंध में प्रतिकर की अदायगी के मामलों का निर्णय करने के लिये अलग-अलग तरह के प्रशासनिक ढांचे बने हुए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) उन राज्यों के नाम जहां वृहत फसल बीमा योजना अभी तक शुरू नहीं की गयी है, वे पंजाब, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम है ।

(ग) विभिन्न राज्यों द्वारा वृहत फसल बीमा योजना लागू करने के प्रयोजन के संबंध में निर्धारित न्यूनतम उपज का आंकलन करने के लिए विभिन्न मानदण्ड नहीं अपनाए गए हैं । विभिन्न राज्यों द्वारा वृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत देय क्षतिपूर्ति दावों के ब्यौरे, भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा प्रत्येक मौसम के अंत में राज्यों द्वारा दिए गए उपज आंकड़ों के आधार पर तयार किए जाते है ।

Inspecting officials for the enforcement of Labour laws

2720. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of LABOUR be pleased to refer to answer to the Unstarred Question 3056 given in the Rajya Sabha on the 19th August, 1988 and state:

(a) whether it is a fact that according to the I.L.O. convention No. 6, the inspecting official for the enforcement of Labour Laws have to be independent body;

(b) if so, whether by merger of Labour Officers with Central Industrial Relation Machinery, the Government have contravened I.L.O. Convention No. 87 by changing service conditions of Officers of Central Industrial Relation Machinery making the Inspecting Officials liable for interchange as Labour Officer; and

(c) how many Senior Regional Labour Commissioners have been transferred as Labour Officers following the merger, and for what reasons?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RADHAKRISHAN MALAVIYA): (a) and (b) The I.L.O. Convention concerning labour inspection in industry is Convention No. 81. The provisions of this Convention are not contravened by the constitution of Central Labour Service and interchangeability of Officers.

(c) Regional Labour Commissioners (Central) and Senior Labour Officers belong to Grade IV of the Central Labour Service and are interchangeable. After constitution of the Service w.e.f. 3-2-1987, two officers who were holding the post of Regional Labour Commissioner (Central) prior to the constitution of the Service, were transferred as Senior Labour Officers for administrative reasons.